



125

न्यायालय राजस्व मंडल ग्रामीण कैम्प भोपाल

प्र.क्र. /12-13 निगरानी

दोघानसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह

जाति दाँगो निवासी अंडियाका
तह. गुलावगंज जिला विदिशा-आवेदक

बनाम

धीरजसिंह, खिलानसिंह, सरदारसिंह,
लक्ष्मणसिंह, रूपसिंह पुत्रगण बहादुरसिंह दाँगो
निवासी अंडियाका तह. गुलावगंज जिला
विदिशा —— अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 7-2-13 न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी
ग्यारसपुर कैम्प गुलावगंज प्र.क्र. 37/07-08 धीरजसिंह आदि विरुद्ध
लक्ष्मणसिंह आदि अंतर्गत धारा 50 भू. रा. संहिता के अंतर्गत ।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं ।

1. यह कि ग्राम अंडियाका में आवेदक संघ अनावेदकगण के पिता के नाम पर खसरा संबंध 583, 502, 376, 300, 304, 306, 314, 315, 318, 325, मूल रकवा 8.65। हेक्टेर भूमि शासकोय रिकार्ड में दर्ज है उनको मृत्यु के बाद उनकी उक्त भूमि पर फोती नामांतरण हुआ जिसकी पंजी क्र. 7 आदेश दिनांक 14-5-96 है जिसमें सभी पक्षकारों के नाम पर उनके पिता के स्थान पर आपसी सहमति से फोती नामांतरण किया गया। नामांतरण के समय आवेदक संघ अनावेदकगण उपस्थित थे उनकी सहमति से फोती नामांतरण तस्दीक किया गया उस बक्त किसी भी पक्ष ने कोई वसीयत पेश नहीं की न हवाला दिया इससे साधित होता है कि फोती नामांतरण होते बक्त तक कोई वसीयत नहीं हुई थी ।

2. यह कि अनावेदकगण ने फोती नामांतरण होने के बाद अनावेदकगण ने 2006-07 तक तहसील न्यायालय में अथवा अन्य कही वसीयत पेश नहीं की संधूं उक्त प्रकरण गतिशील रहते हुये भी तहसील न्यायालय ने मूल वसीयत पेश नहीं की जबकि माननीय तहसीलदार महोदय ने अनावेदकगण को अपने न्यायालय में लगभग 13 अवसर वसीयत पेश करने हेतु दिये किंतु अनावेदकगण ने उनके न्यायालय में वसीयत पेश नहीं की इसके बाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने 15-11-12 को अंतिम आदेश पारित करने के दिन अंतिम आदेश पारित किया ।

[Signature]

करने के अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने अंतिम आदेश पारित कर अनावेदकगण को

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगो 694-पीबीआर/13

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	वार्त्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०.४.१८	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, ग्यारसपुर कैम्प गुलाबगंज के प्रकरण क्रमांक 37/07-08 में पारित आदेश दिनांक 7-2-2013 के विरुद्ध मो प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है। आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के तर्कों को मान्य करते हुए साक्षीगण को बुलाने हेतु तलवाना पेश करने की अनुमति दी है।</p> <p>2/ दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश करने हेतु समय चाहा गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।</p> <p>3/ अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील के दौरान अनावेदकों द्वारा यह आवेदन पेश किये जाने पर कि वसीयत के साक्षीगण फोत हो चुके हैं, इसलिए वे स्वयं एवं एक अन्य साक्षी का कथन कराना चाहते हैं जिसे दे न्यायालय के माध्यम से बुलाना चाहते हैं। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने यह साक्ष्य का अवसर देना न्यायोचित मानते हुए अनावेदकों के तर्क को मान्य कर साक्षी को बुलाने हेतु तलवाना जमा करने की अनुमति दी है तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। उनके इस आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

BSC

(M)

-3-

R. 694 - PBR/13 (फिरी)

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आणि
के हस्ताक्षर

आवेदकों को अपना पक्ष रखने तथा साक्षी के प्रतिपरीक्षण का समुचित अवसर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में अधीनरथ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्षों को सूचना दी जाये तथा अभिलेख वापिस किया जाये।


सदस्य

